# जब दिग्गज भिड़ते हैं : यूएस-चीन विवाद पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 नवम्बर, 2018

**''एपीईसी में यू.एस.-चीन विवाद उनके ट्रेड वॉर के खतरों को दर्शाता है।''**

अपने एक चौथाई शताब्दी से अधिक का इतिहास तोड़ते हुए, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) संगठन ने बिना कोई संयुक्त घोषणा जारी किये हुए संयुक्त शिखर सम्मेलन को समाप्त कर लिया है। इस सम्मेलन में प्रशांत क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई खुल कर सामने आ गई।

इसमें दो गुट थे। एक गुट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का था तो दूसरी ओर चीन था। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच आर्थिक प्रतिद्वंद्विता 21 देशों के शिखर सम्मेलन को दो खंडों में बाँट दिया। इस संघर्ष का मुख्य स्रोत ट्रम्प प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति से निकला, जिसके तहत वाशिंगटन ने अनुचित व्यापार पर शुल्क लगाया।

यह एक अस्पष्ट आरोप था कि चीन वैश्विक व्यापार के खेल मैदान में उच्च स्तर का खेल नहीं खेल रहा है। अमेरिका चीन से बाजार तक आसान पहुंच बढ़ाने और अमेरिकी निगमों के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा प्रदान करने, औद्योगिक सब्सिडी पर कटौती करने और व्यापक स्तर पर 375 अरब डॉलर के व्यापार अंतर को कम करने की मांग कर रहा है।

राष्ट्रपति की तरफ से भाग लेने वाले उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने रणनीतिक रूप से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रों को उन ऋणों का त्याग करने का आग्रह किया जो उन्हें बीजिंग के ऋण जाल में जकड़ सकता है। पेंस ने छोटे देशों को चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशएटिव' (बीआरआई) परियोजना के लालच में नहीं आने की चेतावनी दी, जिसमें निर्माण एवं विकास परियोजनाओं के लिए गरीब देशों को चीन की ओर से धन की पेशकश की गई है।

पेंस ने आरोप लगाया कि यह 'अस्पष्ट' ऋण कर्ज का बोझ बढ़ाएगा। उन्होंने 'एकतरफा' मार्ग बता कर इस परियोजना का मजाक उड़ाया। उन्होंने देशों से इसके बजाय अमेरिका के साथ रहने की अपील की, जो अपने सहयोगियों को कर्ज में नहीं डुबोता है, उनके साथ जबर्दस्ती नहीं करता और उनकी आजादी के साथ समझौता नहीं करता।

इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी ने भी अपने भाषण में अमेरिका के 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के बारे में कहा कि इसमें कोई 'छिपा हुआ एजेंडा' नहीं है। उन्होंने इसे 'चेकबुक कूटनीति' करार दिया। उन्होंने 'अमेरिका प्रथम' व्यापार संरक्षणवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक 'संकीर्ण पहल है' जिसके विफल होने की आशंका है।

हांलाकि, यह सच है कि बीआरआई ने छोटे एशियाई राष्ट्रों और अमेरिका को चिंतित किया है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि चीन एशिया-प्रशांत परिदृश्य को दुनिया भर में आर्थिक प्रावधान सुरक्षित करने के साधन के रूप में देखता है।

यह समझने के लिए कि वैश्विक आर्थिक टाइटन्स का यह संघर्ष विश्व व्यापार प्रणाली के लिए कितना गंभीर साबित हो सकता है, उनके अब तक के पारस्परिक संघर्ष की जांच करनी होगी। गर्मियों में इस समस्या की शुरुआत हुई जब दोनों देशों ने 50 अरब डॉलर के दूसरे आयात के लायक कर शुरू कर दिए, इसके बाद यू.एस. ने 10% टैरिफ के साथ 200 बिलियन डॉलर चीनी निर्यात को घटा दिया, जो साल के अंत तक 25% तक पहुंच गया।

परिणामस्वरूप चीन ने भी 60 बिलियन डॉलर की पारस्परिक कर लगाने के साथ अपना प्रतिशोध लिया। पहले से ही टैरिफ युद्ध के परिणामस्वरूप आईएमएफ ने इस साल के लिए अपने वैश्विक विकास दृष्टिकोण को कम कर दिया है और अगले साल के लिए अपने पूर्वानुमान 3.9% को 0.2 प्रतिशत अंक कम करते हुए 3.7% कर दिया है।

हांलाकि, देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि क्षेत्रीय बैठक में चीन के अधिकारियों ने हंगामा किया हो। इससे पहले इसी वर्ष सितंबर में एक सम्मेलन के दौरान चीन से माफी मांगने को कहा गया था। उस समय चीन के अधिकारी इस बात पर बैठक छोड़कर चले गए थे कि मेजबान ने उनके दूत को अपनी बारी से पहले बोलने की इजाजत नहीं दी थी। पोर्ट मोर्सबी में रविवार को हुए घटनाक्रम और किसी आधिकारिक बयान पर नहीं पहुंच पाने से एपेक की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।

यदि यह जारी रहता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं और व्यापार की मात्रा में कमी आने से कंपनियां नए व्यापारिक मार्गों और भागीदारों की तलाश कर सकती हैं। संस्थागत रूप से, डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय नियम बनाने वाले निकाय अपना अधिकार खो सकते हैं और द्विपक्षीय व्यापार संधि एवं दंडात्मक प्रतिबंध नेटवर्क की एक इंटरलॉकिंग प्रणाली सर्वसम्मति से आधारित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर सकती है।

एशिया इस संघर्ष के केंद्र में होगा क्योंकि इसकें उच्च मूल्य समुद्री व्यापार मार्गों का रणनीतिक नियंत्रण वैश्विक व्यापार प्रभुत्व के चीन के सपने की कुंजी है। एपीईसी शिखर सम्मेलन के बाद दुनिया अभी भी व्यापार युद्ध भंवर के किनारे पर खड़ा है। हांलाकि, अर्जेंटीना में आने वाली जी-20 बैठक में इसमें सुधार की गुंजाईश दिखती है।

## एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

**चर्चा में क्यों?**

- हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार पर बढ़ी तनातनी के चलते एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) फोरम की बैठक बेनतीजा रही।
- एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री को पुलिस बुलानी पड़ी।
- इसके साथ ही एपेक के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि बैठक खत्म होने के बाद संयुक्त आधिकारिक बयान पर भी सहमति नहीं बन पाई।
- इसमें दो गुट थे। एक गुट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का था तो दूसरी ओर चीन था।

**क्या है?**

- APEC का फुल फॉर्म एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation) है। यह एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी।
- इसमें 21 देश सदस्य हैं। इनके नाम हैं- ऑस्ट्रेलिया; ब्रुनेई दारुस्सलाम; कनाडा; चिली; चीन जनवादी गणराज्य; हांगकांग, चीन; इंडोनेशिया; जापान; कोरिया गणराज्य; मलेशिया; मेक्सिको; न्यूजीलैंड; पपुआ न्यू गिनी; पेरू; फिलीपींस; रूसी संघ; सिंगापुर; चीनी ताइपी; थाईलैंड; संयुक्त राज्य अमरीका; वियतनाम।
- इन 21 देशों की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या के लगभग 40% के बराबर है।
- विश्व की सम्पूर्ण GDP का 54% इन देशों के पास है और साथ ही विश्व व्यापार का 44% इन्हीं देशों के बीच होता है।
- इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लोगों की खुशहाली में वृद्धि करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए APEC जिन वस्तुओं को बढ़ावा देता है, वे हैं- संतुलित, समावेशी, सतत, नवप्रवर्तक, सुरक्षित वृद्धि और आर्थिक एकसूत्रता।

**कार्य**

- यह एशिया-प्रशांत के सभी निवासियों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने में सहायता पहुँचाती है।
- यह ग्रामीण समुदायों के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देने तथा महिलाओं को अपने उत्पादों को विदेश में निर्यात करने में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझते हुए सभी देशों को ऊर्जा की बचत करने तथा जंगल और सामुद्रिक संसाधनों के सतत प्रबन्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।
- यह सदस्य देशों को अपने ढंग से इन विषयों में कार्यवाई करने की छूट देता है- आपदा, महामारी और आतंकवाद।

### संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन के सदस्यों की कुल संख्या 21 हैं।
   2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है।
   3. हाल के घटनाक्रम (ट्रेड वॉर) को देखते हुए आईएमएफ ने अगले साल के लिए वैश्विक विकास 3.9 प्रतिशत का पूर्वानुमान लगाया है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

### संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

**प्रश्न: हाल के दिनों में टैरिफ वॉर को लेकर विश्व की दो महाशक्तियों के बीच विभिन्न सम्मेलनों में अंत:विरोध देखने को मिलता है। इस अंत:विरोध से भविष्य में पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों की चर्चा करें। (250 शब्द)**

**नोट :**
20 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2 (d) और 3(c) होगा।